नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 097
दि. 08.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महाराष्ट्र में नगर निकायों के बाद सत्ता का तमाशा अप्राकृतिक गठबंधनों से मचा राजनीतिक भूचाल

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद जो राजनीतिक तस्वीर उभरी है, उसने न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन को असहज कर दिया है, बल्कि राज्य की राजनीति में नैतिकता, सिद्धांत और विचारधारा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन दलों को अब तक एक-दूसरे का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता रहा, वे सत्ता की गणित में अचानक एक मंच पर खड़े नजर आए। भाजपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों का स्थानीय स्तर पर साथ आ जाना राज्य की राजनीति में 'सत्ता की सर्कस' जैसा दृश्य पेश कर रहा है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाते हुए इन अप्राकृतिक गठबंधनों को तुरंत खत्म करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक उठापटक और तेज हो गई है। अंबरनाथ नगर परिषद इस राजनीतिक उलटफेर का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। 60 वार्डों वाली इस नगर परिषद में बहुमत के लिए 31 सदस्यों की जरूरत थी। चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और माना जा रहा था कि परिषद की सत्ता उसी के हाथों में जाएगी। लेकिन नतीजों के बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। भाजपा ने कांग्रेस और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' नाम से एक नया मोर्चा बना लिया। इस गठजोड़ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और नगर परिषद की सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा की ही सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) सत्ता से बाहर हो गई। इसी गठबंधन के समर्थन से भाजपा नेता तेजश्री करंजुले को नगर परिषद की अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाली भाजपा का स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस का कारण बन गया। उद्धव ठाकरे गुट की

शिवसेना ने इसे खुली तौर पर अनैतिक और अवसरवादी राजनीति करार दिया। अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में हालात और भी पेचीदा नजर आए। यहां भाजपा ने 'अकोट विकास मंच' नाम से एक मोर्चा बनाया, जिसमें एआईएमआईएम के साथ-साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दल भी शामिल हो गए। 35 सदस्यीय परिषद में इस मोर्चे के दम पर भाजपा की माया धुले को महापौर चुना गया। भाजपा नेताओं ने सफाई दी कि एआईएमआईएम के पार्षदों ने पार्टी की विचारधारा से अलग होकर भाजपा का समर्थन किया है और इसे औपचारिक गठबंधन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विचारधारा की यह लचीली व्याख्या भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन पार्टी की नीति और विचारधारा के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने स्थानीय नेताओं के इन फैसलों को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन बताते हुए तुरंत ऐसे सभी गठबंधनों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के सख्त संदेश के बाद भाजपा ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अकोट में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी ने अपने ही विधायक प्रकाश भारसाखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि इस कदम से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो विधायक के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

दूसरी ओर, अंबरनाथ में भाजपा के साथ हाथ मिलाने की कीमत कांग्रेस को भी चुकानी पड़ी है। कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा के साथ गठबंधन कर सत्ता में शामिल हुए अपने सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह गठबंधन पार्टी आलाकमान की जानकारी और अनुमति के बिना बनाया गया था, इसलिए न केवल पार्षदों पर कार्रवाई की गई, बल्कि ब्लॉक इकाई को भी भंग कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने साफ कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच किसी भी स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है और अंबरनाथ में बना मोर्चा पूरी तरह असंवैधानिक और अनुशासनहीन कदम था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने भाजपा को 'दोमुंहा केंचुआ' करार देते हुए कहा कि सत्ता के लिए यह पार्टी किसी के भी साथ खड़ी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मीरा-भयंदर जैसे इलाकों में भी एआईएमआईएम का परोक्ष समर्थन लिया है। सचिन अहीर समेत अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा का यह रवैया उसके 'कांग्रेस-मुक्त भारत' जैसे नारों और घोषित विचारधारा के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के बाद बना यह राजनीतिक परिदृश्य केवल स्थानीय सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीति में सिद्धांतों और सत्ता की प्राथमिकताओं के टकराव को भी सामने लाता है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भले ही कुछ गठबंधन टूटते नजर आ रहे हों, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता की राजनीति में स्थानीय स्तर पर विचारधाराएं किस हद तक लचीली हो सकती हैं। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर न केवल नगर निकायों की राजनीति पर, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल सकता है।

28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने के आसार, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला संसद का बजट सत्र इस बार 28 जनवरी से शुरू हो सकता है और 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर सकती हैं। बुधवार को संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बजट सत्र की संभावित तारीखों पर चर्चा की गई, जिसमें संसद के आगामी सत्र की रूपरेखा को लेकर अहम प्रस्ताव रखा गया। सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को आम बजट पेश करने का प्रस्ताव सामने रखा है, हालांकि इन तारीखों पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैठक में बजट सत्र की शुरुआत के लिए दो तारीखों—28 जनवरी और 31 जनवरी—पर विचार हुआ। इनमें से किसी एक तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा। परंपरागत रूप से संसद का बजट सत्र जनवरी के आखिरी सप्ताह

में ही आरंभ होता है, ताकि नए वित्त वर्ष से पहले सभी जरूरी विधायी और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में यह भी संभावना जताई जा रही है कि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सरकार बीते वर्ष की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का खाका पेश करती है, जिसके आधार पर अगले दिन बजट में नीतिगत फैसलों की दिशा साफ होती है। बजट सत्र आमतौर पर दो हिस्सों में आयोजित किया जाता है। पहले चरण में बजट पेश किया जाता है और उस पर सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद कुछ समय का अवकाश रखा जाता है, ताकि संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की गहन समीक्षा कर सकें। दूसरे चरण में इन अनुदान मांगों पर चर्चा और मंजूरी दी जाती है।

इस प्रक्रिया के जरिए बजट को केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि संसद की सामूहिक सहमति से पारित वित्तीय योजना का रूप दिया जाता है। इस बार भी 1 फरवरी को ही केंद्रीय बजट पेश किए जाने की पूरी संभावना है, भले ही उस दिन रविवार हो। पिछले कुछ वर्षों से सरकार वित्तीय प्रक्रियाओं में स्थिरता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए बजट की तारीख में बदलाव से बचती रही है। गौरतलब है कि भारत में लंबे समय तक केंद्रीय बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदलते हुए बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी। इसका उद्देश्य यह था कि बजट के प्रावधान नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही लागू किए जा सकें और सरकारी योजनाओं को समय पर अमल में लाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। यदि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाता है, तो यह उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट होगा। इससे पहले वह कई अहम और चुनौतीपूर्ण दौरों में बजट पेश कर चुकी हैं, जिनमें कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू सुधारों से जुड़ी बड़ी घोषणाएं शामिल रही हैं। इस बार भी देश की आर्थिक वृद्धि, महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे पर निवेश जैसे मुद्दों पर बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं

पुणे पोर्श हादसा: जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कानून से खिलवाड़ के आरोपों पर टिकी देश की निगाहें

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुए पोर्श कार हादसे से जुड़ा मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने गंभीर सवालों के साथ खड़ा हो गया है। मई 2024 में हुई इस दर्दनाक घटना में दो निर्दोष लोगों की मौत ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उन जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा है, जिनमें आरोप है कि जांच को प्रभावित करने के लिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई।

बुधवार को जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयॉन की पीठ ने आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। दोनों आरोपियों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, ये वही लोग हैं जिन पर नाबालिग चालक के खून के नमूनों की जगह किसी और के सैंपल जांच के लिए इस्तेमाल कराने का आरोप है, ताकि यह साबित न हो सके कि हादसे के वक्त वह शराब के नशे में था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को इस मामले में आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। यह मामला 19 मई 2024 की उस रात से जुड़ा है, जब पुणे के पॉश इलाके कल्याणी नगर में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने दो युवकों को कुचल दिया था। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि कार एक 17 वर्षीय नाबालिग चला रहा था और वह कथित तौर पर शराब के नशे में था। हादसे की भयावहता और आरोपी की पृष्ठभूमि सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। लोगों को उम्मीद थी कि कानून सख्ती दिखाएगा, लेकिन शुरुआती घटनाक्रम ने आम जनता को निराश कर दिया।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को बेहद आसान शर्तों पर जमानत दे दी। जमानत की शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था। जैसे ही यह आदेश सामने आया, देशभर में आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों ने सवाल उठाए कि क्या दो लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक निबंध तक सीमित रह गई है। आलोचना इतनी तीखी हुई कि पुणे पुलिस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अपने ही आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना पड़ा। इसके बाद बोर्ड ने अपना फैसला बदला और नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। हालांकि जून 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का आदेश दे दिया, जिससे विवाद और गहरा गया।

मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया जब जांच एजेंसियों ने यह खुलासा किया कि हादसे के बाद नाबालिग के अल्कोहल टेस्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। आरोप है कि ससून जनरल अस्पताल में जांच के दौरान रक्त के नमूनों की अदला-बदली की गई, ताकि नशे की पुष्टि न हो सके। इसी साजिश के तहत आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि आदित्य सूद के रक्त के नमूने उसके पिता के रक्त से बदल दिए गए थे। इस मामले में अस्पताल के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी हुई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई।

इन खुलासों के बाद यह मामला सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं रहा, बल्कि न्याय व्यवस्था, चिकित्सा नैतिकता और प्रभावशाली लोगों के दबाव जैसे बड़े सवालों से जुड़ गया। आम लोगों के मन में यह शंका गहराने लगी कि क्या रसूख और पैसा कानून से ऊपर हो सकते हैं। यही वजह है कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं, तो उसे एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए जाने को इस पूरे मामले में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी और अगली सुनवाई पर पीड़ित परिवारों के साथ-साथ पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

भारत बनेगा दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश, किसानों को मिलेगी नई पहचान : गडकरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के सड़क बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत कृषि अवशेषों से बायो-बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। उन्होंने इसे देश के लिए तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि बताया। गडकरी सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा आयोजित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां इस स्वदेशी तकनीक को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। नितिन गडकरी ने कहा कि यह पहल न केवल सड़क निर्माण के तरीके को बदलेगी, बल्कि किसानों की भूमिका को भी नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेंगे, बल्कि सड़कों के लिए बिटुमेनदाता भी बनेंगे। देश में हर साल पैदा होने वाले करोड़ों टन कृषि कचरे का उपयोग अब सड़क निर्माण जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्य में किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गडकरी ने पराली जलाने की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि अब पराली समस्या नहीं, बल्कि वेल्थ बनेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में पराली जलाने से हर साल गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है। केवल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से करीब 1.6 लाख टन धूल उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए घातक है। नई तकनीक के जरिए 600 मिलियन टन से अधिक कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला जाएगा। उन्होंने इसे 'वेस्ट टू वेल्थ' की सशक्त मिसाल बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो-बिटुमेन के उपयोग से भारत को बड़े आर्थिक लाभ होंगे। वर्तमान में भारत अपनी कुल बिटुमेन जरूरत का लगभग 40 से 50 प्रतिशत आयात करता है, जिस पर हर साल करीब 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 तक देश में बिटुमेन की मांग 100 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। यदि बिटुमेन में केवल 15 प्रतिशत बायो-बिटुमेन का मिश्रण किया जाए, तो इससे हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। यह कदम कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा।

यह स्वदेशी तकनीक सीएसआईआर-सीआरआरआई और सीएसआईआर-देहरादून द्वारा विकसित की गई है, जो पैरोलीसिस प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें धान के भूसे का उपयोग किया जाता है और जीरो वेस्ट मॉडल को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया में कृषि अवशेषों से बायो-ऑयल तैयार किया जाता है, जिसे पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिलाकर बायो-बिटुमेन बनाया जाता है। इसके साथ-साथ बायो-गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और बायो-चार को खेतों में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ बहुउपयोगी भी है।

गडकरी ने बताया कि इस तकनीक का परीक्षण पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अक्टूबर 2024 में जोराहट-शिलांग खंड पर 100 मीटर और नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक किलोमीटर लंबाई

तेलंगाना हाईकोर्ट की रोक से बरकरार रही ब्रह्मोस के महानिदेशक की नियुक्ति, नेतृत्व विवाद पर फिलहाल विराम

(जीएनएस)। हैदराबाद। ब्रह्मोस एयरोस्पेस में नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत ब्रह्मोस के महानिदेशक पद पर जयतीर्थ आर. जोशी की नियुक्ति को रद्द करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि जयतीर्थ आर. जोशी ब्रह्मोस के महानिदेशक पद पर बने रहेंगे। उन्होंने 2 दिसंबर 2024 को इस अहम पद का कार्यभार संभाला था और अब हाईकोर्ट के फैसले से उनकी नियुक्ति को तत्काल राहत मिल गई है।

यह मामला तब चर्चा में आया जब पिछले महीने हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठ ने जोशी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। कैट ने अपने आदेश में रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह इस पद के लिए वरिष्ठतम वैज्ञानिक शिवसुब्रह्मण्यम नम्बी नायडू के दावे पर दोबारा विचार करे। नम्बी नायडू उन तीन उम्मीदवारों में शामिल थे, जिन्हें इस शीर्ष पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। उन्होंने नवंबर 2024 में अधिकरण में याचिका दायर कर यह तर्क दिया था कि वह जयतीर्थ आर. जोशी से लगभग सात वर्ष वरिष्ठ हैं और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें महानिदेशक पद पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।

नम्बी नायडू की याचिका में यह भी कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में वरिष्ठता के सिद्धांत की अनदेखी की गई, जिससे उनके साथ अन्याय हुआ। इसी आधार पर कैट ने जोशी की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह मामला रक्षा प्रतिष्ठान और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। ब्रह्मोस जैसी अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक रक्षा परियोजना में नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने इस विवाद को और भी गंभीर बना दिया था।

हालांकि, कैट के आदेश के खिलाफ जयतीर्थ आर. जोशी और संबंधित पक्षों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल जोशी की नियुक्ति वैध बनी रहेगी और वह अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। हाईकोर्ट की इस अंतरिम राहत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास से जुड़े अधिकारियों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे ब्रह्मोस परियोजना में प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी।

यह नेतृत्व विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति आदेशों को क्रियान्वित कर रहा है। ब्रह्मोस भारत की सबसे उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परियोजना मानी जाती है, जिसकी मांग देश के भीतर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। ऐसे में शीर्ष स्तर पर अनिश्चितता और कानूनी विवाद परियोजना की गति और रणनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकते थे।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के इस फैसले से फिलहाल उस आशंका पर विराम लगा है। हालांकि, यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। फिलहाल इतना तय है कि जयतीर्थ आर. जोशी ब्रह्मोस के महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे और संगठन अपने महत्वपूर्ण रक्षा दायित्वों को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के आगे बढ़ा सकेगा।

संपादकीय

कानून व्यवस्था की पोल खोलती हत्याएं

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक शृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफलताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाइटैक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है। इसके अलावा बंदूकों पर लगाम लगाने के लिये कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास में व्यापक निवेश करने तथा भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से करने होंगे। ऐसे राज्य में जो एक दशक तक चरमपंथ की त्रासदी झेल चुका हो, अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम वक्त की मांग है। राज्य के सत्ताधीशों को चाहिए कि पंजाब द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को गैंगस्टरों, ड्रग माफिया और आतंकवादियों के घातक गठजोड़ का शिकार कदापि नहीं होने दें।

गैर जिम्मेदार तंत्र की नाकामी से उपजा संकट

> “पेयजल लाइनों का पुराना होना, मरम्मत और देखभाल का अभाव, खराब योजना और डिजाइन, जल संचय का अपर्याप्त प्रबंधन, शुद्धीकरण के लिए व्यवस्था और निगरानी की कमी, और घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच की व्यवस्था न होना, साथ ही भ्रष्टाचार - इन सभी कारणों से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है।

बीते दिनों इंदौर शहर के भगीरथपुरा क्षेत्र में सीवर अवशेष प्रदूषित पानी के सेवन के कारण 16 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अस्पतालों में लगभग 200 लोग भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है और 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इंदौर में बोरिंग के पानी में भी मल-मूत्र का बैक्टीरिया पाया गया है। लोग अब एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी साफ पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं।

जब बात सबसे स्वच्छ शहर की हो, तो इस स्थिति में देश के अन्य शहरों की हालत क्या होगी? यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात के गांधीनगर को भी इंदौर जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। यहां दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। दिल्ली के लोग भी हर साल दूषित पेय जलापूर्ति की समस्या से जूझते हैं। कई बस्तियों में गंदे पानी की आपूर्ति का मामला अभी भी एनजीटी में विचाराधीन है। एनजीटी की सख्ती के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड ने इस इलाके की दशकों पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने का काम शुरू किया है। यह बात भी गौर करने लायक है कि दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों में लिए गए 33 सैंपल फेल पाए गए हैं। इंदौर का मामला पूरी तरह से सरकारी लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। काफी दिनों से इंदौर के भगीरथपुरा के लोग दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन और अधिकारियों पर उनकी शिकायतों का कोई असर ही नहीं हुआ। उनकी नींद तब खुली जब दूषित पानी पीने से दस्त और उलटी से लोगों की मौत होने लगी और पीड़ित लोगों की तादाद 3000 के पार पहुंच गयी। उस समय हाई कोर्ट ने तत्काल लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराने और पीड़ितों का हरसंभव निःशुल्क इलाज कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही, नगर निगम के अपर आयुक्त, जल कार्य निगम के अधीक्षण अभियंता को निलंबित और आयुक्त को हटाने के साथ तीन नगर आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इलाके में सप्लाई किये जाने वाले नर्मदा के पानी के सैंपल लेने का काम शुरू किया। जांच में मल-मूत्र मिश्रित होने की पुष्टि हुई तब नगर निगम ने वहां के बोरिंग के पानी के सैंपल लिए। बोरिंग के 69 सैंपलों में से 35 जांच में फेल पाये गये। नर्मदा जल जांच के बाद अब बोरिंग के पानी में भी फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आयी है, जिससे हैजा फैला। इंदौर मेडिकल कालेज की रिपोर्ट भी पुष्टि करती है कि भगीरथपुरा में एक पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने का पानी दूषित हुआ और यह बीमारी फैली। अस्पतालों में भर्ती पीड़ित रोगियों में टायफायड के लक्षण भी पाये गये हैं। डाक्टरों का तो इन पीडितों में हैपेटाइटिस-ए जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने का अंदेशा है। वहीं उलटी-दस्त के संक्रमण के कारण कुछ मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। ऐसे रोगियों की स्थिति सुधरने में दूसरे रोगियों की तुलना में काफी समय लगेगा।

सरकार हाईकोर्ट में दावा कर रही है कि हालात काबू में हैं जबकि अस्पतालों में पीड़ितों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। दुखद यह है कि अभी भी प्रभावित क्षेत्र भगीरथपुरा में पेयजल संकट बरकरार है। एनएचआरसी ने भी इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

देश में नीति आयोग की मानें तो हर साल दूषित पानी पीने से दो लाख लोगों की मौत होती है, विशेषज्ञ इनकी तादाद कहीं ज्यादा बताते हैं। नीति आयोग की मानें तो देश में तकरीबन 60 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। इससे 6 फीसदी जीडीपी का नुकसान होता है। पेयजल की गुणवत्ता के मामले में हमारे देश का दुनिया के 122 देशों में 120वां स्थान है। असलियत में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतें विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती प्रतीत होती हैं। इससे जल जीवन मिशन की नाकामी साबित होती है।

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था में नाकामी में सरकारी अनियमितताओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उसका जीता-जागता सबूत हैं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और सीवर लाइन के लिए स्वीकृत 1.93 लाख करोड़ की परियोजनाओं में अभी तक केवल 44 हजार करोड़ के काम पूरे हो पाना। जबकि इनकी अवधि इसी मार्च में पूरी हो रही है।

पीने के पानी की लाइनों का पुराना होना, मरम्मत और देखभाल का अभाव, खराब योजना और डिजाइन, जल संचय का अपर्याप्त प्रबंधन, शुद्धीकरण के लिए व्यवस्था और निगरानी की कमी, और उपभोक्ता स्तर पर घरों से पानी के सैंपल लेकर जांच की व्यवस्था न होना, साथ ही भ्रष्टाचार, इन सभी कारणों से जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है। जनता मजबूरी में प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह कि जब पेय जलापूर्ति राज्य की प्राथमिकता में ही न हो, तब शुद्ध पानी सपना ही बना रहेगा।

प्रेरणा

छेनी, हथौड़ा और आत्मा की मूर्ति

एक बार की बात है, एक कला प्रेमी महान इतालवी मूर्तिकार माइकल एंजेलो की विश्वप्रसिद्ध 'डेविड' की मूर्ति को निहारते हुए ठिठक गया। संगमरमर का वह विशाल पिंड जैसे सांस ले रहा हो, जैसे पत्थर नहीं बल्कि जीवित मनुष्य हो। उसकी आँखों में विस्मय था, मन में कौतूहल। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और विनम्रता से पूछ बैठा—महोदय, आपने पत्थर के एक साधारण और बेजान टुकड़े से इतनी जीवंत और सुंदर मूर्ति का निर्माण कैसे किया? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। माइकल एंजेलो ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया—मैंने कोई निर्माण नहीं किया। यह मूर्ति तो पहले से ही उस पत्थर में विद्यमान थी। मैंने तो बस पत्थर के उस अनावश्यक हिस्से को छेनी-हथौड़े से काट कर हटा दिया, जो मूर्ति नहीं था। जैसे ही फालतू परतें हटीं, उसमें छिपा सत्य अपने आप प्रकट हो गया।

यह उत्तर केवल कला का नहीं, जीवन का भी गूढ़ दर्शन है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए हमें बहुत कुछ जोड़ना होगा—नई डिग्रियाँ, नए पद, नई उपलब्धियाँ, नए रिश्ते, नया दिखावा। पर क्या सच में पूर्णता जोड़ने से आती है? या फिर वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस अनावश्यक परतों से ढकी हुई? माइकल एंजेलो का कथन हमें यही समझाता है कि सृजन बाहर से नहीं, भीतर से होता है; और भीतर का सृजन जोड़ने से नहीं, हटाने से संभव होता है।

मनुष्य के भीतर भी एक सुंदर, सशक्त और शांत मूर्ति छिपी होती है। बचपन में जब हम सरल होते हैं, तब वह मूर्ति अपेक्षाकृत साफ दिखाई देती है। समय के साथ समाज, प्रतिस्पर्धा, भय और असुरक्षा की परतें उस पर चढ़ती जाती हैं। क्रोध हमें भीतर से कठोर बना देता है, अहंकार हमारी दृष्टि को संकीर्ण कर देता है और ईर्ष्या हमारे हृदय को विषाक्त कर देती है। ये सभी भाव किसी बाहरी शत्रु की तरह नहीं आते, बल्कि हमारे ही भीतर पत्थर की परतों की तरह जमते जाते हैं। परिणाम यह होता है कि भीतर का श्रेष्ठ स्वरूप दब जाता है और हम स्वयं को ही पहचान नहीं पाते।

आज का मनुष्य लगातार कुछ बनने की दौड़ में है। बेहतर दिखना है, बेहतर साबित होना है, दूसरों से आगे निकलना है। इस दौड़ में वह यह भूल जाता है कि असली विकास भीतर की यात्रा है। यदि एक मूर्तिकार हर वार के साथ सावधानी न बरते, तो वह सुंदर मूर्ति को ही तोड़ सकता है। इसी तरह, यदि हम बिना समझ के अपने जीवन में कुछ भी जोड़ते चले जाएँ—अनावश्यक इच्छाएँ, झूठे मानदंड, दूसरों से तुलना—तो हम अपने भीतर छिपी सुंदरता को ही नुकसान पहुँचा देते हैं।

क्रोध एक ऐसी परत है जो सबसे पहले दिखाई देती है। यह हमें तात्कालिक शक्ति का भ्रम देती है, पर भीतर से खोखला कर देती है। क्रोध में कही गई बातों का पश्चाताप लंबे समय तक मन को कचोटता है। जब हम क्रोध की परत को हटाते हैं, तो उसके नीचे करुणा और समझ का उजास मिलता है। अहंकार दूसरी परत है, जो हमें ऊँचा दिखाती जरूर है, पर दूसरों से दूर कर देती है। अहंकार के कारण हम सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पहले से ही पर्याप्त हैं। जैसे ही अहंकार हटता है, विनम्रता जन्म लेती है और विनम्रता के साथ ज्ञान का द्वार खुलता है।

ईर्ष्या शायद सबसे सूक्ष्म परत है। यह हमें दूसरों की सफलता से दुखी करती है और अपनी उपलब्धियों को भी फीका बना देती है। ईर्ष्या में डूबा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब हम ईर्ष्या को हटाते हैं, तो भीतर संतोष का भाव आता है। हम दूसरों की सफलता में भी प्रेरणा देखने लगते हैं और अपनी यात्रा पर भरोसा करने लगते हैं। यह हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। जैसे पत्थर से अनावश्यक हिस्सा हटाने में धैर्य, कौशल और समय लगता है, वैसे ही आत्मपरिष्कार में भी निरंतर अभ्यास चाहिए। आत्मचिंतन इस प्रक्रिया की छेनी है और संयम उसका हथौड़ा। हर दिन थोड़ा-सा रुककर स्वयं से प्रश्न करना—क्या मेरा यह विचार मुझे हल्का कर रहा है या बोझिल? क्या मेरा व्यवहार मेरे भीतर की शांति बढ़ा रहा है या घटा रहा है? धीरे-धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि क्या हटाना है। यह किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है; प्रश्न यह है कि हम उसे परत की तरह जमा लेते हैं या सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं।

माइकल एंजेलो का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखें। हर व्यक्ति के भीतर एक सुंदर मूर्ति है, चाहे उस पर कितनी ही खुरदुरी परतें क्यों न चढ़ी हों। यदि हम केवल बाहरी खुरदरापन देखें, तो हम उसके सत्य को नहीं पहचान पाएँगे। करुणा की दृष्टि वही पारखी दृष्टि है, जो पत्थर में छिपी मूर्ति को पहचान लेती है।

अंततः जीवन का उद्देश्य स्वयं को गढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रकट करना है। जो हम वास्तव में हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अनावश्यक पत्थरों को हटाते जाते हैं, तो भीतर से सहजता, प्रेम और शांति का स्वरूप सामने आता है। तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह लगता है—जहाँ हर दिन हम अपनी आत्मा की मूर्ति को थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। यही पारखी दृष्टि है, यही जीवन की सच्ची कला।

सोमनाथ मंदिर हमारी सभ्यतागत चेतना का प्रतीक, स्मृतियां कभी मिटती नहीं और सच्ची आस्था कभी हारती नहीं

सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के एक हजार वर्ष पूर्ण होना हमें उस शाश्वत चेतना का स्मरण कराता है, जिसने सदियों से भारत के आत्मा को पोषित किया। सोमनाथ की यह यात्रा प्रमाण है कि हमारी सभ्यतागत चेतना वह 'अक्षयवट' है, जिसे कोई भी आक्रांता नष्ट नहीं कर सका। महमूद गजनवी द्वारा इस पवित्र मंदिर पर किया गया आक्रमण मात्र एक स्थापत्य संरचना पर आघात नहीं, बल्कि वह उस गौरवशाली सभ्यतागत पहचान को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास था, जो युगों-युगों से इस पूण्यभूमि को भारत के रूप में परिभाषित करती आई है। वर्ष 1026 का वह घाव गहरा था, जिसने न केवल मंदिर की शिलाओं को खंडित किया, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान को भी चुनौती दी थी। हालांकि समय की धारा ने यह सिद्ध किया कि भारत की सांस्कृतिक चेतना कभी समाप्त नहीं होती।

छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के संकल्प से लेकर ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा की रक्षा तक, यह यात्रा निरंतर जारी रही। स्वराज की इस लौ को छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मेरे पूर्वज महाराजा महादजी सिंधिया जैसे हजारों योद्धाओं ने अनवरत अपने शौर्य से जलाए रखा। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिकार अठारहवीं शताब्दी में तब देखने को मिला, जब महाराजा महादजी सिंधिया की शक्ति ने भारत के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध (1761) की भीषण त्रासदी के पश्चात, जब महादजी महाराज ने अपने परिवार के सोलह सदस्यों को खोया तो यह मराठाओं की शक्ति के अस्तित्व की कठोर परीक्षा थी।

तब महादजी महाराज ने अदम्य धैर्य, निरंतर संघर्ष और दूरदर्शी रणनीति के बल पर 10 फरवरी, 1771 को दिल्ली के लालकिले पर मराठा-भगवा ध्वज फहराया। यह विजय मात्र एक नगर की प्राप्ति नहीं, बल्कि मराठा-सनातन स्वाभिमान और राजनीतिक प्रभुत्व की पुनः स्थापना का प्रतीक भी थी। वर्ष 1771 से 1803 तक दिल्ली पर सिंधिया वंश का प्रभावी नियंत्रण रहा। वर्ष 1785 में महाराजा महादजी सिंधिया ने दिल्ली विजय के बाद लाहौर विजय अभियान आरंभ किया। उन्होंने सिखों के साथ रणनीतिक गठबंधन और स्थानीय समर्थन के बल पर सशक्त युद्धनीति अपनाई। 29 मई, 1785 को दिल्ली से भारी तोपखाने के साथ लाहौर की ओर कूच करते हुए उन्होंने अफगान गढ़ी को घेर लिया। जुलाई में हुए लगातार संघर्षों में अफगान सेनापति शाह गुलजार हुसैन, परवेज खान और अशरफ अली मारे गए। मानसून के बाद सितंबर में निर्णायक विजय मिली और मोहम्मद शाह अब्दाली को मराठाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।

इस विजय के साथ अटक से कटक तक और प्रयागराज से भरूच तक 'हिंदवी स्वराज्य' की सुदृढ़ और प्रतिष्ठित स्थापना हुई। 1785 का लाहौर युद्ध महाराजा महादजी सिंधिया की अद्वितीय सैन्य कुशलता का प्रमाण था, जिसने अफगान सेनाओं में भय उत्पन्न किया। उनके शासन में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तथा भरूच से प्रयागराज तक विस्तृत हुआ और भगवा ध्वज सर्वत्र लहराया। इस बार लाहौर की धरती पर उन्होंने विजय पताका फहराई और अफगान सेनाओं को सिंधु के पार खदेड़ा। इस युद्ध में महादजी महाराजा ने सदियों पहले 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर किए गए उस आघात का वह सभ्यतागत प्रतिशोध लिया, जिसने भारत के आत्मा पर गहरी चोट की थी।

महाराजा महादजी सिंधिया लाहौर में मोहम्मद शाह अब्दाली के महल से वे ऐतिहासिक चांदी के द्वार वापस लेकर आए, जिन्हें गजनवी सोमनाथ से लूटकर ले गया था। उन्होंने भारी सुरक्षा में उन द्वारों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भेजने की व्यवस्था की, परंतु उन द्वारों के सोमनाथ पहुंचने पर पुजारियों का कहना था कि वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहने के कारण उन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर महादजी महाराज ने उन्हें उज्जैन भेजा, जहां गोपाल मंदिर में उन द्वारों की प्रतिष्ठा की गई।

760 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने सीमाओं के पार जाकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आक्रांताओं के चंगुल से वापस लाने का अदम्य साहस दिखाया। उन द्वारों का भारत लौटना 'सांस्कृतिक न्याय' की पुनर्स्थापना थी। 1234–1235 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा ध्वस्त किए गए महाकाल मंदिर का 1734 में उज्जैन में महादजी महाराज के पिता महाराजा राणोजीराव सिंधिया द्वारा शून्य से पुनर्निर्माण कराया गया और आगे चलकर स्वयं महादजी महाराज ने उसे भव्यता एवं गौरव का स्वरूप प्रदान किया। यही वह वैचारिक भूमि थी, जिसने सोमनाथ के गौरव को सहेजने का आधार तैयार किया।

स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण आधुनिक भारत के आत्मविश्वास का प्रखर चेहरा बना। 12 नवंबर, 1947 को लौहपुरुष सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनरुद्धार का ऐतिहासिक संकल्प लिया। सोमनाथ ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक केएम मुंशी के प्रयासों और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद के सान्निध्य में 11 मई, 1951 को जब ज्योतिर्लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया ने देखा कि भारत अब अपनी सभ्यतागत जड़ों से विमुख नहीं होगा। सोमनाथ आंदोलन से प्रेरणा लेकर 1990 में राम-रथ यात्रा सोमनाथ से आरंभ हुई और 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अयोध्या की ओर बढ़ी। इस ऐतिहासिक यात्रा के उद्घाटन में मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयाराजे सिंधिया का योगदान भी रहा है, मानो इतिहास स्वयं अपनी निरंतरता को साक्षात अनुभव कर रहा हो।

सोमनाथ कारिडोर का निर्माण इस सत्य का साक्ष्य है कि हम अपनी आस्था के केंद्रों को न केवल सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित भी कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में सोमनाथ से लेकर राम जन्मभूमि तक जो कायाकल्प हुआ है, वह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने वाला एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र बन चुका है। सोमनाथ की यह एक हजार वर्ष की यात्रा हमें सिखाती है कि स्मृतियां कभी मिटती नहीं और सच्ची आस्था कभी हारती नहीं।

अभियान

मां रुक्मिणी की कृपा से खुले सौभाग्य के द्वार

सनातन परंपरा में स्त्री शक्ति को केवल पूज्य नहीं, बल्कि जीवन की गति और संतुलन का मूल माना गया है। जब इस शक्ति का स्वरूप लक्ष्मी के रूप में प्रकट होता है, तब वह केवल धन की देवी नहीं रहती, बल्कि सौभाग्य, स्थिरता और संतोष का आधार बन जाती है। मां रुक्मिणी इसी लक्ष्मी तत्व का वह दिव्य रूप हैं, जिसमें प्रेम, धर्म और त्याग का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वे श्रीकृष्ण की अर्धांगिनी हैं, लेकिन उससे भी आगे वे उस चेतना की प्रतीक हैं, जो जीवन को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। श्री रुक्मिणी अष्टकम उसी चेतना का स्तवन है, जिसके नियमित पाठ से विवाह, दांपत्य और धन-संपदा से जुड़े अनेक अवरोधों के शांत होने की मान्यता है। मां रुक्मिणी का जीवन स्वयं एक आध्यात्मिक संदेश है। उन्होंने राजसी वैभव, सामाजिक दबाव और भय को त्यागकर श्रीकृष्ण का वरण किया, क्योंकि उनके लिए प्रेम और धर्म सर्वोपरि थे। यही कारण है कि उन्हें लक्ष्मी का अवतार कहा गया। लक्ष्मी केवल धन नहीं देतीं, बल्कि सही चुनाव करने की बुद्धि भी प्रदान करती हैं। जब कोई साधक श्री रुक्मिणी अष्टकम का पाठ करता है, तो वह इसी बुद्धि और विवेक को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यह स्तोत्र व्यक्ति को भीतर से तैयार करता है, ताकि वह योग्य संबंध, सही अवसर और स्थायी सुख को ग्रहण कर सके।

विवाह में विलंब या बार-बार आने वाली बाधाएं आज के समय में एक सामान्य समस्या बन चुकी हैं। कुंडली के दोष, पारिवारिक परिस्थितियां या स्वयं व्यक्ति के भीतर छिपे भय इस विलंब के कारण बन सकते हैं। श्री रुक्मिणी अष्टकम का पाठ इन सभी स्तरों पर कार्य करता है। यह मन के भीतर जमी असुरक्षा को शांत करता है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का संचार करता है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और सही समय पर सही संबंध स्वतः जीवन में प्रवेश करता है। यही कारण है कि परंपरा में इस स्तोत्र को विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने वाला माना गया है।

दांपत्य जीवन केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि दो चेतनाओं का संगम है। जब इस संगम में अहंकार, अपेक्षाएं और संवाद की कमी आ जाती है, तब संबंधों में दरारें पड़ने लगती हैं। मां रुक्मिणी की कृपा यहां एक मधुर संतुलन स्थापित करती है। वे सिखाती हैं कि प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। श्री रुक्मिणी अष्टकम का नियमित पाठ पति-पत्नी के बीच सहनशीलता और समझ को बढ़ाता है। इससे छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम होते हैं और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है। यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। मां रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूप मानने के कारण इस स्तोत्र का संबंध धन और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यह समृद्धि केवल अचानक धन प्राप्ति तक सीमित नहीं रहती। यह आर्थिक स्थिरता, कार्यक्षेत्र में संतुलन और संसाधनों के सही उपयोग के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। यही कृतज्ञता लक्ष्मी तत्व को स्थिर करती है। जहां असंतोष होता है, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं, और जहां संतोष होता है, वहां समृद्धि स्वयं आती है। पाठ विधि को लेकर शास्त्रों में सरलता और शुद्धता पर बल दिया गया है। किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शांत मन से मां रुक्मिणी का स्मरण करते हुए पाठ करना पर्याप्त माना गया है। यदि घर में श्रीकृष्ण और मां रुक्मिणी का चित्र हो, तो उनके सामने दीपक जलाकर पाठ करने से मन और अधिक एकाग्र होता है। शुक्रवार का दिन इस साधना के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी तत्व से जुड़ा है। उस दिन सात्त्विक आहार और संयमित व्यवहार साधना को और प्रभावी बनाता है।

कुछ लोग पूछते हैं कि क्या केवल पाठ करने से जीवन की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसका उत्तर है कि पाठ कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जब व्यक्ति नियमित रूप से किसी दिव्य स्तोत्र का स्मरण करता है, तो उसका मन उसी ऊर्जा के अनुरूप ढलने लगता है। श्री रुक्मिणी अष्टकम व्यक्ति को धैर्य, प्रेम और विनम्रता की ऊर्जा से जोड़ता है। यही ऊर्जा उसके कर्मों और निर्णयों में परिलक्षित होती है। परिणामस्वरूप जीवन की दिशा धीरे-धीरे सकारात्मक होने लगती है।

इस स्तोत्र का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर का वातावरण भी प्रभावित होता है। जहां पहले तनाव और अस्थिरता रहती थी, वहां धीरे-धीरे शांति और सौहार्द का अनुभव होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मां रुक्मिणी गृहस्थ जीवन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का केंद्र बन जाता है। आर्थिक चिंता, वैवाहिक तनाव और मानसिक अशांति एक साथ शांत होने लगती है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्री रुक्मिणी अष्टकम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। जब भीतर श्रद्धा और संतुलन होता है, तब बाहर की दुनिया भी उसी के अनुरूप व्यवस्थित होने लगती है। मां रुक्मिणी का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं, जहां धर्म और प्रेम साथ-साथ चलते हैं।

आज के समय में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना धैर्य मांगती है। श्री रुक्मिणी अष्टकम का पाठ भी समय के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। यह जीवन में अचानक उथल-पुथल नहीं करता, बल्कि धीरे-धीरे अवरोधों को हटाता है। जैसे नदी चुपचाप पत्थरों को घिसती हुई रास्ता बना लेती है, वैसे ही यह स्तोत्र जीवन की कठिनाइयों को शांत तरीके से सरल बनाता है।

अंततः श्री रुक्मिणी अष्टकम केवल विवाह या धन की कामना तक सीमित नहीं है। यह जीवन को सौम्यता, संतुलन और स्थायित्व प्रदान करने का साधन है। जो साधक श्रद्धा के साथ मां रुक्मिणी का स्मरण करता है, उसके जीवन में सौभाग्य के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। यह सौभाग्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होता है। यही मां रुक्मिणी की सच्ची दिव्य कृपा है, जो जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

महाप्रबंधक पश्चिम एवं मध्य रेलवे ने साबरमती महेसाणा–पालनपुर सेक्शन का किया विस्तृत निरीक्षण

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे द्वारा रेल संरक्षा एवं आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर अग्रसर विभिन्न विकासात्मक एवं संरक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक 07.01.2026 को महाप्रबंधक पश्चिम एवं मध्य रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ साबरमती–कलोल–महेसाणा–पालनपुर रेल खंड का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान साबरमती से पालनपुर के बीच रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, छोटे एवं प्रमुख पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग, सेक्शन कर्व्स तथा विभिन्न संरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों के साथ संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कलोल, महेसाणा एवं पालनपुर स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। साथ ही मास्टर केबिन, बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम सहित विभिन्न आधारभूत संरचना कार्यों का निरीक्षण किया गया।

साबरमती–कलोल खंड के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 240 (SPL) का गहन निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त कलोल रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रगति पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया। डांगरवा स्टेशन यार्ड में पॉइंट्स संख्या 107 (किमी 743/294) तथा कर्व संख्या 116 की संरक्षा जांच की गई। साथ ही प्रमुख पुल संख्या 965 DN (कॉम्पोज़िट गर्डर) का निरीक्षण किया गया। खारी नदी पर स्थित मेजर ब्रिज संख्या 965 (किमी 719/28-8) तथा पी-वे गैंग संख्या 13 एवं 14 का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक ने गैंगमैनों से संवाद कर कार्य के दौरान उपयोग किए जा रहे सेफ्टी उपकरणों- जैसे सेफ्टी शूज, जैकेट एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं समय पर आपूर्ति की जानकारी ली।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महेसाणा स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही आरपीएफ पोस्ट, आरआरआई रूम, टीआरडी डिपो, एसएसपी कार्यालय, रेलवे हेल्थ यूनिट तथा रेलवे कॉलोनी की सुविधाओं का अवलोकन कर यात्री एवं कर्मचारियों से जुड़ी सुविधाओं का आकलन किया गया। उंझा–कामली के बीच RUB नं. 932A एवं ब्रिज संख्या 927D के स्पान का भी निरीक्षण किया गया।

मीडिया से संवाद करते हुए महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के निरीक्षणों के माध्यम से रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग तथा कर्व्स का विभिन्न संरक्षा मानकों के अनुरूप वार्षिक परीक्षण किया जाता है, जिससे सुरक्षित एवं सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि आंबलियासन–विजापुर तथा आदरज मोटी–विजापुर के बीच गेज परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस सेक्शन का CRS निरीक्षण भी संपन्न हो गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस मार्ग पर नई रेल सेवाओं का परिचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

महेसाणा–पालनपुर सेक्शन में रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य के पूर्ण होने से ट्रेन परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे के कुल 1337 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशन शामिल हैं।

अहमदाबाद एवं साबरमती स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 9 से 12 तथा साबरमती स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर कार्य प्रगति पर है, जो मार्च–अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके पश्चात दोनों स्टेशनों पर अधिक ट्रेनों का ठहराव संभव होगा, जिससे नई ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों के लिए रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से लगभग दोगुना करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे से लगभग 256 ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो आगामी पाँच वर्षों में बढ़कर लगभग 450 हो जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, रेलवे फाटक मुक्त अभियान के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर उनके स्थान पर आरयूबी/आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। बेचराजी–रणुज रेलवे लाइन पर शीघ्र ही CRS निरीक्षण किया जाएगा, जिसके उपरांत इस सेक्शन पर भी रेल परिचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

महाप्रबंधक ने सिद्धपुर में नवनिर्मित गुड्स शेड प्रशासनिक कार्यालय उद्घाटन किया। सिद्धपुर में नवनिर्मित जी+1 गुड्स शेड क्षेत्र में माल परिवहन संभाल क्षमता को सुदृढ़ करने तथा परिचालन दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक गुड्स शेड परिचालन आवश्यकताओं एवं हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस सुविधा में सीओएस कक्ष, एफओआईएस कक्ष, व्यापारियों के लिए कक्ष तथा कैंटीन शामिल हैं, जिससे माल परिचालन का सुचारु समन्वय सुनिश्चित होगा और उपयोगकर्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, सुविधा और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने हेतु पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। साथ ही सिद्धपुर में नवनिर्मित रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स का रेल कर्मचारी की बालिका से उद्घाटन करवाया गया। रेलकर्मी श्री पींटू भारती, श्री मुन्नाराम और श्री रामभरण को क्वार्टर्स की चाबियाँ सौंपी गईं।

सिद्धपुर–पालनपुर सेक्शन में 130 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल भी किया गया। पालनपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त पालनपुर स्टेशन पर SPART तथा न्यू पालनपुर में रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकसित कार्यों का अवलोकन किया गया तथा लोकोमोटिव शेड साबरमती टीम द्वारा निर्मित वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनर (VAT क्लीनर) मशीन का परीक्षण भी किया गया।

अपने निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री गुप्ता ने रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों, एसोसिएशनों, जन प्रतिनिधियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा गणमान्य नागरिकों से भी भेंट कर संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यालय से आए विभिन्न विभागों के प्रधान विभागाध्यक्षों सहित मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त कार्य के संबंध में 09/10 जनवरी, 2026 की रात को कांदिवली स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर पॉइंट्स के इंसर्शन एवं डिस्मैंटलिंग के लिए 23:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 10/11 जनवरी, 2026 की रात को कांदिवली और मालाड स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर पॉइंट 101 के इंसर्शन के लिए मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर 01:00 बजे से 06:30 बजे तक तथा अप स्लो लाइन पर 01:00 बजे से 04:00 बजे तक रहेगा।

उपर्युक्त ब्लॉकों, पांचवीं लाइन के निलंबन तथा गति प्रतिबंध लगाए जाने के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित होंगी।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

री-शेड्यूल होने वाली ट्रेनें:

1. 10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद–दादर एक्सप्रेस अपने मार्ग में 20 मिनट री-शेड्यूल होगी।
2. 10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19218 वेरावल–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 45 मिनट री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन वेरावल से 12:35 बजे प्रस्थान करेगी।
3. 11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद 30 मिनट री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन 06:10 बजे प्रस्थान करेगी।
4. 11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस, 1 घंटा री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन 06:10 बजे प्रस्थान करेगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली उपनगरीय ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

श्रम संहिताओं और तकनीक से खनन क्षेत्र में सुरक्षा को मिलेगा नया बल, श्रमिकों के संरक्षण पर सरकार का जोर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार खनन क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को लेकर नई दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग से खदानों में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए देशभर में एकरूप और सख्त सुरक्षा व्यवस्था समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके और श्रमिकों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके।

धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के 125वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शोभा करंदलाजे ने डीजीएमएस की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ सौ साल की इस यात्रा में डीजीएमएस ने न केवल खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को स्थापित किया, बल्कि अधिकारियों और श्रमिकों के समर्पण, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का भी प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि कठिन और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खदान कर्मियों के प्रयासों ने देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और खनन गतिविधियों को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि खदानों में समान सुरक्षा मानकों को लागू कराने में डीजीएमएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्रीय कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सख्ती से पालन हो, क्योंकि नियमों का ईमानदारी से अनुपालन ही दुर्घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी नवाचारों और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से खनन कार्य को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। श्रम सुधारों पर बात करते हुए शोभा करंदलाजे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई चार नई श्रम संहिताओं के माध्यम से 29 पुराने और बिखरे हुए कानूनों का एकीकरण किया गया है। इन संहिताओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। उन्होंने विशेष रूप से संविदा श्रमिकों का उल्लेख करते हुए कहा कि नई श्रम संहिताओं के जरिए उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे में लाया गया है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, बीमा और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। मंत्री ने डीजीएमएस से आग्रह किया कि वह इन संहिताओं के बारे में खनन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों और श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाए और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करे।

यजुर फाइबर्स का आईपीओ बाजार में उतरा, निवेशकों के लिए 120 करोड़ रुपये के मौके का खुला रास्ता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। फाइबर प्रोसेसिंग क्षेत्र की उभरती कंपनी यजुर फाइबर्स ने बुधवार को शेयर बाजार में अपने कदम रखते हुए 120.41 करोड़ रुपये का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम निवेशकों के लिए खोल दिया है। यह आईपीओ 9 जनवरी तक खुला रहेगा, जिसके बाद 12 जनवरी को शेयरों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। सफल आवंटन के बाद 13 जनवरी को शेयर निवेशकों के डीमैट खातों में जमा किए जाएंगे और 14 जनवरी को कंपनी के शेयर बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इस निर्गम के जरिए कंपनी न केवल पूंजी जुटाना चाहती है, बल्कि पूंजी बाजार में अपनी मौजूदगी को भी मजबूत करना चाहती है।

कंपनी ने आईपीओ के लिए 168 से 174 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में 800 शेयर रखे गए हैं और खुदरा निवेशकों को न्यूनतम दो लॉट यानी 1,600 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम करीब 2.78 लाख रुपये का निवेश करना पड़ेगा। इस इश्यू के तहत कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले कुल 69.20 लाख नए शेयर जारी कर रही है, जिससे जुटाई गई राशि का उपयोग कारोबारी विस्तार और अन्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।

शेयरों के आवंटन ढांचे की बात करें तो इसमें खुदरा निवेशकों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा रखा गया है। कुल इश्यू का 65.87 प्रतिशत रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए 28.20 प्रतिशत, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 0.92 प्रतिशत और मार्केट मेकर के लिए 5.01 प्रतिशत हिस्सा तय किया गया है। इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर की भूमिका हॉरिजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड निभा रही है, जबकि एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। गिरीराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लिए मार्केट मेकर है।

वित्तीय मोर्चे पर यजुर फाइबर्स का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है, जो निवेशकों के लिए आकर्षण का एक अहम कारण बन सकता है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 3.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.27 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद 2024-25 में कंपनी के मुनाफे में तेज उछाल देखने को मिला और यह 11.68 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में भी कंपनी की कमाई की रफ्तार बनी हुई है और 30 नवंबर 2025 तक कंपनी 7.12 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमा चुकी है।

राजस्व के स्तर पर भी कंपनी ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2022-23 में जहां यजुर फाइबर्स का राजस्व 61.84 करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर 141.99 करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़े कंपनी के कारोबार के विस्तार और बाजार में बढ़ती मांग को दर्शाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फाइबर प्रोसेसिंग सेक्टर में बढ़ते अवसरों का लाभ कंपनी को आगे भी मिल सकता है।

कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कर्ज और रिजर्व दोनों में बदलाव देखने को मिला है। 2024-25 में कंपनी का कुल कर्ज 66.18 करोड़ रुपये रहा, जो 30 नवंबर 2025 तक बढ़कर 73.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर रिजर्व और सरप्लस में भी इजाफा हुआ है, जो 2022-23 में 28.65 करोड़ रुपये था और मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर 40.56 करोड़ रुपये हो गया है। EBITDA के स्तर पर भी कंपनी ने मजबूती दिखाई है और 2024-25 में यह 18.85 करोड़ रुपये रहा, जो संचालन क्षमता में सुधार को दर्शाता है।

कुल मिलाकर यजुर फाइबर्स का यह आईपीओ ऐसे समय में बाजार में आया है, जब निवेशक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और ग्रोथ संभावनाओं वाली कंपनियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लगातार बढ़ता मुनाफा, राजस्व में तेज वृद्धि और फाइबर प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में मौजूदगी इसे निवेशकों के लिए एक अहम अवसर बनाती है, हालांकि अंतिम फैसला निवेशकों को अपने जोखिम आकलन और निवेश रणनीति के अनुसार करना होगा।

भारत 2040 तक चंद्रमा पर भेजेगा अपने अंतरिक्ष यात्री: इसरो पूर्व प्रमुख का दावा

(जीएनएस)। अहमदाबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार ने बुधवार को एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत 2040 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित वापस लाने की दिशा में काम कर रहा है। यह घोषणा उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 5वें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में की।

कुमार ने अपने भाषण में बताया कि अब से लेकर 2040 तक भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में कई मिशन संचालित किए जाएंगे। इनमें न केवल चंद्रमा पर मानव मिशन शामिल हैं, बल्कि भारत अपने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास मुख्य रूप से सामाजिक और वैज्ञानिक लाभ के उद्देश्य से किया है, न कि सैन्य उद्देश्यों के लिए।

इसरो के पूर्व प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना मात्र नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करना भी है। उन्होंने बताया कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशनों के लिए विकसित तकनीकें न केवल अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि पृथ्वी पर वैज्ञानिक प्रयोगों और संसाधनों के अध्ययन में भी सहायक होंगी।

कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि चंद्रमा पर भारतीय मिशन का लक्ष्य केवल 'उतारना और लौटाना' नहीं है, बल्कि वहां स्थायी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र स्थापित करना भी है।

सोना वायदा में 867 रुपये, चांदी वायदा में 4344 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 85 रुपये की गिरावट

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 157127.24 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 41377.01 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 115744.23 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 36260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2510.04 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 32940.37 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 139140 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 139140 रुपये और नीचे में 137879 रुपये पर पहुंचकर, 139083 रुपये के पिछले बंद के सामने 867 रुपये या 0.62 फीसदी गिरकर 138216 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 322 रुपये या 0.28 फीसदी गिरकर 113156 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 66 रुपये या 0.47 फीसदी गिरकर 14117 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138947 रुपये के भाव पर खूलकर, 138991 रुपये के दिन के उच्च और 137779 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 856 रुपये या 0.62 फीसदी गिरकर 138149 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 139498 रुपये के भाव पर खूलकर, 139950 रुपये के दिन के उच्च और 138550 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139595 रुपये के पिछले बंद के सामने 665 रुपये या 0.48 फीसदी गिरकर 138930 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 257599 रुपये के भाव पर खूलकर, 259692 रुपये के दिन के उच्च और 251729 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 258811 रुपये के पिछले बंद के सामने 4344 रुपये या 1.68 फीसदी लुढ़ककर 254467 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3912 रुपये या 1.5 फीसदी गिरकर 256625 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3881 रुपये या 1.49 फीसदी घटकर 256645 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 41377.01 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 115744.23 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 32940.37 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36260 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 5264.51 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 13.55 रुपये या 1.01 फीसदी गिरकर 1324.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 2.8 रुपये या 0.89 फीसदी गिरकर 312.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.56 फीसदी औंधकर 313.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 1.85 रुपये या 0.96 फीसदी की तेजी के संग 195.4 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3166.99 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5200 रुपये के भाव पर खूलकर, 5200 रुपये के दिन के उच्च और 5060 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 85 रुपये या 1.63 फीसदी गिरकर 5125 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 87 रुपये या 1.67 फीसदी गिरकर 5123 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 312.2 रुपये के भाव पर खूलकर, 317.4 रुपये के दिन के उच्च और 308.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 306.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 8.8 रुपये या 2.87 फीसदी की मजबूती के साथ 315.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 8.8 रुपये या 2.87 फीसदी की तेजी के संग 315.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 1004 रुपये पर खूलकर, 14.7 रुपये या 1.45 फीसदी औंधकर 1001 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11735.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21204.89 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4046.49 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 520.52 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 259.89 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 383.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1074.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2080.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19361 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74097 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28229 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 418166 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 46872 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16229 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39985 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 102333 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22359 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 46848 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 36630 पॉइंट पर खूलकर, 36650 के उच्च और 36260 के नीचले स्तर को छूकर, 454 पॉइंट घटकर 36260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 46 रुपये की गिरावट के साथ 115.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.1 रुपये की बढ़त के साथ 22.95 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 183 रुपये की गिरावट के साथ 710.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2370.5 रुपये की गिरावट के साथ 12815.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15.39 रुपये की गिरावट के साथ 28.67 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4 रुपये की गिरावट के साथ 9.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 43.1 रुपये की बढ़त के साथ 97.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.25 रुपये की गिरावट के साथ 17.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 72.5 रुपये की बढ़त के साथ 368 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1922 रुपये की बढ़त के साथ 12750 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2 पैसे के सुधार के साथ 31.57 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 60 पैसे की नरमी के साथ 2.87 रुपये हुआ।

तेलंगाना की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम, बीआरएस की निलंबित एमएलसी के. कविता का इस्तीफा स्वीकार

(जीएनएस)। हैदराबाद। तेलंगाना राजनीति में बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) की निलंबित नेता के. कविता का इस्तीफा एक नए राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दे रहा है। विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंदर रेड्डी ने उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। परिषद सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, के. कविता का इस्तीफा 6 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना गया है। इस कदम के साथ ही निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की सीट रिक्त हो गई है, जिस पर भविष्य में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के. कविता ने वर्ष 2021 में निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुनाव जीता था। हालांकि उन्होंने 3 सितंबर, 2025 को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उस समय इसे तकनीकी कारणों और प्रक्रियात्मक देरी के चलते स्वीकार नहीं किया गया। इसके चलते इस्तीफा कई महीनों तक लंबित रहा और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। लंबे इंतजार के बाद कविता ने 5 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से विधान परिषद अध्यक्ष से मुलाकात कर इस्तीफे की स्वीकृति के लिए आग्रह किया। अध्यक्ष ने तुरंत निर्णय लेते हुए इस्तीफे को मंजूर कर दिया।

बीआरएस से निलंबन और पारिवारिक विवाद

के. कविता को सितंबर 2025 में उनकी पार्टी बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन का कारण पार्टी और परिवार के भीतर बढ़ते विवाद थे। कविता ने अपने चचेरे भाइयों टी. हरीश राव और जे. संतोष कुमार पर आरोप लगाया था कि वे कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बहाने उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस आरोप-प्रत्यारोप के बाद पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेद या पारिवारिक टकराव नहीं है, बल्कि बीआरएस के भीतर नेतृत्व और सत्ता के समीकरण पर भी सवाल खड़ा करता है। यह घटना यह दर्शाती है कि पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व टीम और स्थानीय इकाइयों के बीच तालमेल में खटास आ रही है।

इस्तीफे के निहितार्थ और उपचुनाव की संभावना

कविता के इस्तीफे के साथ ही निजामाबाद की विधान परिषद की सीट रिक्त हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने की संभावना है, जो स्थानीय राजनीति में हलचल ला सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सीट के उपचुनाव में बीआरएस, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवार उतार सकते हैं। इससे तेलंगाना में क्षेत्रीय राजनीति की दिशा और पार्टी के भीतर नेतृत्व के स्थायित्व पर भी असर पड़ सकता है। बीआरएस के अंदर यह घटना पार्टी की छवि के लिए चुनौती भी बन सकती है। पार्टी ने अब तक इस विवाद को कम करने की कोशिश की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस्तीफा और निलंबन की प्रक्रिया ने पारिवारिक और संगठनात्मक मतभेदों को सार्वजनिक किया। इसका प्रभाव केवल निजामाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी चुनावों और पार्टी की रणनीतिक दिशा पर भी दिखाई देगा।

राजनीतिक विश्लेषण

विश्लेषकों का मानना है कि के. कविता का इस्तीफा बीआरएस के भीतर असंतोष को उजागर करता है। पार्टी के भीतर विरोधियों और समर्थकों के बीच तनाव को यह इस्तीफा और बढ़ा सकता है। वहीं, इसे एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है कि पार्टी अब आंतरिक विवादों को नियंत्रित करने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की रणनीतियों, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मतदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर तेलंगाना की राजनीतिक तस्वीर में नए समीकरण बन सकते हैं। कुल मिलाकर, के. कविता का इस्तीफा न केवल निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे तेलंगाना की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह इस्तीफा बीआरएस के आंतरिक संतुलन, नेतृत्व की छवि और भविष्य में होने वाले उपचुनावों के परिणामों पर गहरा असर डाल सकता है। आने वाले महीनों में यह देखने वाली बात होगी कि पार्टी अपने संगठनात्मक विवादों को कैसे सुलझाती है और किस तरह से आगामी राजनीतिक घटनाओं का सामना करती है।

10 जनवरी को 13वां मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प, 800 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य

(जीएनएस)। सूरत। शहर में स्वास्थ्य और मानव सेवा के क्षेत्र में एक और बड़ी पहल के तहत सूरत फाइनेंस एसोसिएशन द्वारा 10 जनवरी, शनिवार को 13वां मेगा ब्लड डोनेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन रिंग रोड स्थित अजंता शॉपिंग सेंटर के ए और बी विंग पार्किंग परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस मेगा रक्तदान शिविर में शहर के विभिन्न ब्लड बैंकों की टीमों का सहयोग भी रहेगा, ताकि रक्तदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो और अधिक से अधिक रक्त इकाइयाँ सुरक्षित रूप से संग्रहित की जा सकें। शिविर के प्रमुख प्रभारी सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष रक्तदान शिविर का लक्ष्य 800 यूनिट रक्त का संग्रह है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में रक्तदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को उपहार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार रक्तदाताओं के लिए विशेष पहल की गई है, जिसके तहत प्रत्येक रक्तदाता को 1 लाख रुपये की बीमा राशि वाली व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भी प्रदान की जाएगी। रक्तदान शिविर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों ने शहर की सामाजिक संस्थाओं, किन्नर समाज के अग्रणियों, रिक्शा और टेम्पो यूनियनों सहित अन्य संगठनों को भी आमंत्रित किया है। इससे शिविर में भागीदारी बढ़ेगी और रक्तदान की प्रक्रिया के माध्यम से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। सूरत फाइनेंस एसोसिएशन ने अजंता शॉपिंग सेंटर में अब तक आयोजित किए गए शिविरों में हजारों यूनिट रक्त का सफल संग्रह किया है, जो कि समाज में मानवीय सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प में गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष जंखना पटेल, सूरत पुलिस आयुक्त अनूपमसिंह गहलोत, जॉइंट पुलिस आयुक्त जमीर और फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हकीम भी उपस्थित रहेंगे। शिविर के आयोजन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में संतोक नहर, अनिल कंकारिया, नरेश कोठारी, अनिल मेहता, ललित चौधरी, बजरंगसिंह कविया सहित सूरत फाइनेंस एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सूरत: सुवाली बीच फेस्टिवल-2026 का आगाज 9 जनवरी से तटीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने और समुद्री इलाकों को आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के प्रयासों के तहत सूरत के सुवाली तट पर तीन दिवसीय 'सुवाली बीच फेस्टिवल-2026' का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक किया जाएगा। यह आयोजन गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन और सूरत जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन 9 जनवरी को शाम 5 बजे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल करेंगे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीपभाई देसाई ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में सुवाली बीच को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। फेस्टिवल का उद्देश्य कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना और पर्यटकों को समुद्र तट के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद प्रदान करना है। फेस्टिवल के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। 9 से 11 जनवरी तक, प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इच्छापोर हाईवे से मोरा हाईवे चौराहा होते हुए एलएंडटी मार्ग तक का रास्ता वन-वे रहेगा और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए 19 रूटों पर सिटी बस और एसटी बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 800 पुलिस और ट्रैफिक कर्मी, साथ ही फायर ब्रिगेड, लाइफगार्ड, एम्बुलेंस और हेल्थ टीमें स्टैंडबाय रहेंगी। फेस्टिवल में ऊंट और घोड़े की सवारी, जीप राइडिंग, पतंगबाजी, रस्साकशी और देसी व पारंपरिक खेल आयोजित होंगे। इसके अलावा फूड कोर्ट, क्राफ्ट स्टॉल, फोटो कॉर्नर और एंटरटेनमेंट ज़ोन सहित कुल 130 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां पर्यटक समुद्र की लहरों के बीच घूमते हुए खाने-पीने और खरीदारी का आनंद ले सकेंगे। फूड कोर्ट में नागली डिश, डांगी डिश, उंबाडियू, बाजरा समेत पारंपरिक और आधुनिक व्यंजन उपलब्ध होंगे।

सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 9 जनवरी को शाम 5.30 बजे ओसमान मीर और आमिर मीर, 10 जनवरी को शाम 7 बजे भूमि त्रिवेदी, और 11 जनवरी को शाम 7 बजे सातवाणी त्रिवेदी अपनी प्रस्तुति देंगे। बच्चों के लिए अलग से मनोरंजन ज़ोन और परिवार एवं दोस्तों के लिए सेल्फी पॉइंट भी उपलब्ध होगा।

संदीपभाई देसाई ने बताया कि सुवाली बीच फेस्टिवल-2026 पर्यटकों को संस्कृति, संगीत, खेल और समुद्र के मनोरम वातावरण का एक साथ अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। यह फेस्टिवल न केवल सूरत के तटीय पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय स्टॉल संचालकों और क्षेत्रवासियों को आजीविका का भी लाभ पहुंचाएगा।

फेस्टिवल में एडवेंचर स्पोर्ट्स, शॉपिंग, खान-पान और पारिवारिक मनोरंजन सभी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजकों का कहना है कि सुवाली बीच फेस्टिवल-2026 एक ऐसा मंच साबित होगा जहां पर्यटक समुद्र तट की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और खेल गतिविधियों का भी अनुभव कर सकेंगे।

यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार देते हुए एक लंबा विशेष रिपोर्ट-लेख तैयार कर दूँ, जिसमें फेस्टिवल के आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का गहराई से विश्लेषण हो, जो अखबार के लिए 2500–3000 शब्द का लेख बन सके। क्या मैं ऐसा कर दूँ?

गुजरात: गांधीनगर में टाइफाइड का कहर, मरीजों की संख्या बढ़कर 144 स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया बड़े पैमाने पर सर्वे और रोकथाम अभियान

(जीएनएस)। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हाल के दिनों में मरीजों की संख्या 144 तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मौजूदा समय में गांधीनगर सिविल अस्पताल में 85 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 59 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेक्टर-24, 26, 28 और आदिवासी इलाकों में 85 टीमें घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं। इन टीमों का उद्देश्य संक्रमित लोगों की पहचान करना, उनकी स्थिति पर नजर रखना और उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही लोगों को क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस पैकेट वितरित किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण के फैलने की संभावना कम हो सके।

जल आपूर्ति विभाग ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल क्लोरीनीकरण बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। लगातार पानी के नमूने लिए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीने के पानी में कोई बैक्टीरिया या संक्रमण न हो। इस कार्य के माध्यम से टाइफाइड के फैलाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने टाइफाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि स्थिति में जल्द सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इसके बाद, सड़क एवं भवन विभाग और नगर निगम ने मिलकर जल लाइनों में रिसाव का पता लगाया और तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि जल आपूर्ति में रिसाव और अव्यवस्थित स्वच्छता टाइफाइड के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण हैं। वहीं, विपक्ष ने प्रशासन पर टाइफाइड के वास्तविक आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और बीमारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

गांधीनगर नगर निगम (GMC) ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि अब तक भर्ती किए गए 133 मरीजों में से 45 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ज्यादातर प्रभावित मरीज बच्चे और युवा थे। नगर निगम ने एक अफवाह का खंडन भी किया जिसमें कहा जा रहा था कि टाइफाइड से एक बच्चे की मौत हुई है। नगर निगम ने X पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत स्थिर है और कोई भी गंभीर मामला नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि टाइफाइड के मामलों में वृद्धि मुख्य रूप से गंदा पानी, अव्यवस्थित जल आपूर्ति और स्वच्छता की कमी के कारण हुई है। इसके अलावा बारिश के मौसम में जल स्रोतों में बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे साफ पानी पिएं, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध लक्षण जैसे तेज बुखार, पेट दर्द, उल्टी या दस्त होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि टाइफाइड का समय पर उपचार होने पर यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इलाज में देरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लगातार सख्त निगरानी और रोकथाम अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, पानी की जांच, लोगों को जागरूक करना और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि अगर नागरिक प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, तो संक्रमण पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सकता है।

गांधीनगर में टाइफाइड के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अस्पताल में मरीजों का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वच्छता, साफ पानी, और नियमित निगरानी से ही लंबे समय में इस तरह के संक्रमण को रोका जा सकता है।

इस समय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहर में टाइफाइड का फैलाव तेजी से न बढ़े। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सरकारी हेल्पलाइन और स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क बनाए रखें और घरों में स्वच्छ पानी और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

भावनगर रेलवे मंडल की वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ,संरक्षा, यात्री सुविधाओं, आधुनिकरण एवं राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने वर्ष 2025 के दौरान रेल संरक्षा, यात्री सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा राजस्व अर्जन के क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से मंडल ने सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक रेल सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

संरक्षा एवं आधारभूत ढांचे में सशक्त सुधार

भावनगर मंडल में रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025 के दौरान 17 लेवल क्रॉसिंग का उन्मूलन आरओबी/आरयूबी निर्माण, डायवर्जन एवं प्रत्यक्ष बंदीकरण के माध्यम से किया गया। इस अवधि में 5 आरयूबी एवं 1 आरओबी का निर्माण पूर्ण हुआ। यात्रियों की सुविधा हेतु सिहोर जंक्शन पर नया फुट ओवर ब्रिज लोकार्पित किया गया तथा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 12 नए एफओबी प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं।

अतिक्रमण रोकने हेतु 9.245 किलोमीटर बाउंड्री वॉल का निर्माण तथा जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दामनगर–लीलिया मोटा खंड में अतिरिक्त वाटर-वे ब्रिज का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महुवा, राजुला जं., जामजोधपुर, सिहोर जं., लींबडी एवं पालिताना स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया।

सुरक्षा, आधुनिकीकरण एवं बेहतर यात्रा अनुभव

रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD) प्रणाली लिलिया मोटा, राणपुर, तरसई एवं चोकी स्टेशनों पर स्थापित की गई। खोडियार मंदिर स्टेशन पर 29.10.2025 को इलेक्ट्रॉनिक इन-मोशन वेइंग सिस्टम चालू किया गया, जिससे ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ।

यात्रियों की सुरक्षा एवं आराम को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों के रेक ICF से आधुनिक LHB कोचों में परिवर्तित किए गए। इसके अतिरिक्त भावनगर–अयोध्या कैंट के बीच नई साप्ताहिक LHB ट्रेन सेवा 03.08.2025 से प्रारंभ की गई। वेरावल-साबरमती के बीच 26.05.2025 से "वंदे भारत एक्सप्रेस" (सप्ताह में 6 दिन, गुरूवार को छोड़कर) शुरू की गई है। इसके अलावा पोरबंदर-राजकोट के बीच 14.11.2025 से 02 नई यात्री ट्रेन भी शुरू की गई है। भविष्य की योजनाओं में 136 करोड़ की लागत से राणावाव में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो तथा 98 करोड़ की लागत से अदितपरा (पोरबंदर) में आधुनिक बूट लॉन्ड्री का प्रस्ताव शामिल है।

यात्रियों की सुरक्षा एवं मानवीय सेवा

RPF भावनगर मंडल द्वारा वर्ष 2025 में यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए गए। ऑपरेशन अमानत के तहत 39.80 लाख से अधिक मूल्य की खोई हुई संपत्ति यात्रियों को सुरक्षित लौटाई गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत 35 बच्चों को रेस्क्यू कर परिजनों से मिलाया गया। रेल संपत्ति चोरी, अवैध यात्रा, अतिक्रमण, स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु निरंतर कार्रवाई एवं जन-जागरूकता अभियान चलाए गए। एक उल्लेखनीय मानवीय उदाहरण में, RPF कर्मी द्वारा दिनांक 30.04.2025 को गोंडल स्टेशन पर समय पर CPR देकर एक यात्री की जान बचाई गई, जिसकी व्यापक सराहना हुई।

यात्री सुविधाएँ एवं राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि

भावनगर मंडल ने यात्री सुविधाओं पर 170 करोड़ से अधिक का निवेश कर डिजिटल उद्घोषणा प्रणाली, गाइडेंस बोर्ड, एफओबी, प्लेटफॉर्म उन्नयन एवं स्टेशन पुनर्विकास कार्य पूर्ण किए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी से दिसंबर 2025 तक) में:

- कुल राजस्व 1375.94 करोड़ (जनवरी से दिसंबर 2025 तक) प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 अप्रैल से दिसंबर-2025 तक 1061.36 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।
- 29.50 करोड़ का सर्वाधिक मासिक (नवंबर-2025) एवं 1.31 करोड़ का सर्वाधिक दैनिक (29.10.2025) यात्री राजस्व दर्ज किया गया है तथा माल ढुलाई में भी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की गईं हैं।
- एक माह में सर्वाधिक उर्वरक के 94 रेक लोड कर 46.83 करोड़ (दिसंबर-2025 में) प्राप्त हुआ है।
- एक माह में सर्वाधिक एलपीजी के 77 रेक लोड कर 21.92 करोड़ का राजस्व अप्रैल-2025 में प्राप्त हुआ है।
- टिकट जांच से एक दिन में 9.05 लाख (15.10.2025) का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ
- एक ही EFT में टिकट जांच स्टाफ द्वारा अब तक की सर्वाधिक वसूली — 78,060/-, श्री राजन कुमार सिंह, सीटीआई/वेरावल द्वारा दिनांक 22.12.2025 को की गई।
- NFR में 14.5% एवं संड्री रेवेन्यू में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- पहली बार गेम जोन जूनागढ़ में 19.11.2025 से शुरू किया गया है।

भावनगर मंडल की अन्य उपलब्धियां

- भावनगर परा रेलवे स्टेशन पर यात्री लिफ्ट का कमीशनिंग।
- नये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में 135.3KWp, कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में 50.6 KWp कुल क्षमता 185.9 KWp का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
- लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेनों का रिकॉर्ड: एक माह में सर्वाधिक PPSP से 43 ट्रेनों का परिचालन।
- 68वीं पेंशन अदालत (दिसंबर-2025) में 225 मामलों का निस्तारण।
- कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर हेल्प डेस्क कियोस्क स्थापित किए गये हैं।
- LC-35 (सरखेज–मोरैया) का इंटरलॉकिंग कार्य 30.12.2025 को सफलतापूर्वक कमीशंड।
- धोला-सुरेन्द्रनगर सेक्शन में बोटाद स्टेशन पर ट्रैक मेंटेनेंस डिपो का 11.11.2025 को कमीशनिंग किया गया।
- मंडलीय रेल चिकित्सालय (DRH) भावनगर में नवजात शिशुओं के लिए फोटोथेरेपी यूनिट का कमीशनिंग; पीलिया (हाइपरबिलिरुबिनेमिया) के उपचार में प्रभावी लाभ।
- वर्ष 2025 के दौरान 04 (भावनगर परा, राणपुर, वीरपुर एवं सिहोर जं.) FOB तैयार हो चुके हैं, 12 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है और 7 स्टेशनों के लिए कार्य प्रस्तावित है।
- मंडल के 16 स्टेशनों पर 40 लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है तथा 6 लिफ्ट प्रस्तावित है।
- वर्ष 2025 के दौरान 12 स्टेशनों पर कोच इंडिकेटर लगाए जा चुके हैं, 21 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।
- मंडल के 12 स्टेशनों पर प्रतिक्षालय (Waiting Room) बनाए जा चुके हैं, 3 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।
- प्लेटफार्म को हाई लेवल करना अथवा विस्तारित करने का कार्य 17 स्टेशनों पर पूर्ण हो चुका है, 03 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है तथा 47 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
- पेंशनरों को पेंशन से सम्बंधित होने वाली समस्याओं का सही समय पर उचित समाधान किया जाता है।
- वित्त अनुभाग, लेखा विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान कुल 4085 मामलों/प्रस्तावों की गहन जाँच की गई। उक्त अवधि में किए गए प्रस्तावों के माध्यम से कुल 98.80 करोड़ की बचत हुई।
- भावनगर मंडल द्वारा वर्ष 2025 में किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप रेल संरक्षा, यात्री सुविधा, सेवा गुणवत्ता, समयपालन एवं राजस्व अर्जन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित हुए हैं। पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय रेल सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के 41 कार्यों के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसरंचना निधि से 1078 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए

- **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा गांधीनगर में नवंबर-2025 में आयोजित बैठक की फलश्रुति**
- **कुल 564.57 किलोमीटर लंबाई में वाइडनिंग, स्ट्रेंदनिंग, रिसरफेसिंग तथा स्ट्रक्चर के विभिन्न कार्य शुरू किए जाएंगे**
- **कनेक्टिविटी तथा ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अधिक गति मिलेगी, पीएम गति शक्ति अंतर्गत लॉजिस्टिक्स परिवहन में सरलता होगी**

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर, 07 जनवरी : भारत सरकार की केन्द्रीय सड़क एवं अवसरंचना निधि (सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड- सीआरआईएफ) से गुजरात को राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1078.13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

गुजरात में राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्यों के लिए आवंटित की गई इस बड़ी राशि से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर कनेक्टिविटी तथा ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को गति देने का दृष्टिकोण साकार होगा। इतना ही नहीं; पीएम गति शक्ति अंतर्गत लॉजिस्टिक्स परिवहन में सरलता होगी और वह तेज बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राज्य के सड़क मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गत नवंबर-2025 में गांधीनगर में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक की फलश्रुति के रूप में गुजरात को 1078.13 करोड़ रुपए की यह राशि राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्य शुरू करने के लिए आवंटित की गई है।

सीआईआरएफ की जो यह राशि राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है, उससे कुल 564.57 किलोमीटर लंबाई में विभिन्न 41 कार्य शुरू किए जाने वाले हैं।

तद्अनुसार; पाटण, कच्छ, बनासकाँठा, खेडा, महीसागर, छोटा उदेपुर, वलसाड, अमरेली, जामनगर तथा वडोदरा जिलों में राज्य राजमार्गों पर 229.20 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण के 11 कार्य शुरू करने के लिए 636 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।

सड़क सुदृढ़ीकरण तथा पुनः सतहीकरण के जो 23 कार्य 335.37 किलोमीटर में 408.33 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले हैं; उनमें अहमदाबाद, खेडा, आणंद, अरवल्ली, महीसागर, तापी, नवसारी, देवभूमि द्वारका, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, सूरत तथा जामनगर जिलों के कार्यों का समावेश होता है।

इन कार्यों के अतिरिक्त; केन्द्रीय सड़क एवं अवसरंचना निधि से स्ट्रक्चर के (ढाँचों से जुड़े) जिन 7 कार्यों के लिए 33.80 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं; उनमें तापी, सूरत तथा डांग जिलों के कार्य शामिल किए जाएंगे।

तिलकवाड़ा स्टेशन का अपग्रेडेशन, यात्रियों के लिए नई सौगात,सेक्शन कैपेसिटी में होगी वृद्धि, अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन संभव

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के डभोई और एकतानगर स्टेशनों के बीच स्थित तिलकवाड़ा स्टेशन को D-क्लास (नॉन-ब्लॉक) स्टेशन से B-क्लास (ब्लॉक) स्टेशन में अपग्रेड करने का कार्य प्रगति पर है। अब यह स्टेशन साधारण स्टॉपिंग पॉइंट से उन्नत सिग्नलिंग, एक बेहतर ऑपरेशनल क्षमता और अधिक यात्री सुविधाओं वाला स्टेशन बन जायेगा, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी।

वडोदरा मंडल में स्थित एकतानगर भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टेचू ऑफ़ यूनिटी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में वडोदरा और एकतानगर के बीच ट्रेन का परिचालन किया जाता है। तिलकवाड़ा को B-क्लास स्टेशन में बदलने से एकतानगर और चांदोद के बीच मौजूदा सिंगल ब्लॉक सेक्शन दो ब्लॉक सेक्शन में बंट जाएगा, यानी एकतानगर – तिलकवाड़ा और तिलकवाड़ा –चांदोद। एक साधारण हॉल्ट से एक फंक्शनल ब्लॉक स्टेशन में बदलने से चांदोद और एकतानगर के बीच ट्रेन परिचालन क्षमता बढ़ेगी, जिससे संरक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही सेक्शन कैपेसिटी बढ़ने से इस सेक्शन में और अधिक ट्रेनों को परिचालित करने का विकल्प मिलेगा। भविष्य में, ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर, तिलकवाड़ा एक फायदेमंद ऑपरेशनल पॉइंट के तौर पर काम करेगा, जिससे ट्रेन रेगुलेशन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। एकतानगर से शुरू होने वाली ट्रेनों का लाईन क्लियर के लिए रुकने का समय कम हो जाएगा, जिससे ऑपरेशन आसान होगा और समय की पाबंदी बेहतर होगी।

तिलकवाड़ा स्टेशन पर एक लूप लाइन का भी निर्माण किया गया है, जिससे लाइन क्षमता बढ़ेगी। ट्रेन को लूप लाइन या साइडिंग में लेकर एक अतिरिक्त ट्रेन को क्रॉसओवर देकर परिचालित कर सकेंगे। B-क्लास (ब्लॉक स्टेशन) बनने पर तिलकवाड़ा में होम/स्टार्टर सिग्नल, पॉइंट्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना होगी। पॉइंट्स और सिग्नल के सुरक्षित संचालन के लिए तिलकवाड़ा स्टेशन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना की जा रही है। ऑपरेशन मैनेज करने के लिए रेलवे स्टाफ की तैनाती होगी।

B-क्लास स्टेशन बनने से तिलकवाड़ा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में भी इज़ाफा होगा, यात्रिओं को स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल, वेटिंग रूम और टिकट काउंटर जैसी सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे यात्रिओं का सफ़र और सुखकर होगा। स्टेशन पर एक हाई-लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान ज़्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।

अपग्रेड होने से पहले डभोई और एकतानगर के बीच तिलकवाड़ा एक D-क्लास (फ्लैग स्टेशन) स्टेशन था, जहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और कुछ बुनियादी सुविधाएं थी। फ्लैग स्टेशन होने के कारण कोई सिग्नल नहीं था और ऑपरेशन के लिए कोई समर्पित रेलवे स्टाफ नहीं था।